



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2000/अग्रहायण 28, 1922

No. 820]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2000/AGRAHAYANA 28, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2000

का.आ. 1132(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन की अध्यक्षता में "विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन इस बात का न्यायनिर्णयन करने के लिए करती है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रण्ट ऑफ असम (उल्फा) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं।

[फा. सं. 11011/65/2000-एन.ई.-IV]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2000

S.O. 1132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) as Unlawful Association consisting of Justice Manmohan Sarin, Judge of Delhi High Court.

[File No. 11011/65/2000-NE. IV]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.

